

स्थानीय शासन में नेतृत्व की सामाजिक पृष्ठभूमि

कोमल पारीक*

स्थानीय शासन का वर्तमान युग में आमजन के लिए अत्यन्त महत्व हैं क्योंकि यह प्रजातंत्र की आधार शिला भी है। स्थानीय शासन सबसे महत्वपूर्ण है फिर भी ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही अंगों में हम ये नहीं कह सकते कि भारत में स्थानीय सरकारें सक्रिय क्रियाशील दक्ष एवं पूर्णतया निपुण है। भारत के संविधान में हुए 73 वें व 74 वें संशोधन से स्थानीय शासन की संस्थाओं की प्रकृति में आए इस परिवर्तन से लोकतंत्र को धरातल के आम आदमी तक पहुँचाने में मदद मिल रही है।

किसी भी देश का स्थानीय शासन प्रायः दो इकाईयों में विभाजित है— नगरीय एवं ग्रामीण। नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका) का होता है इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व पंचायती राज की त्रिस्तरीय रचना (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) द्वारा वहन किया जाता है।

प्रस्तुत आलेख में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि नगरीय एवं ग्रामीण नेतृत्वकर्ताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है उनमें क्या अन्तर है दोनों ही इकाईयों के नेतृत्व में क्या तथ्य उभरकर सामने आये है। जाति, धर्म, आयु व्यवसाय, एवं शिक्षा में दोनों इकाईयों में क्या अन्तर स्पष्ट होता है इसके लिए शोधार्थी ने एक नगरपरिषद (किशनगढ़) एवं 4-5 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण किया एवं प्रतिनिधियों से कतिपय प्रश्न किए जिसका सर्वेक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार इस आलेख में प्रस्तुत किया जा रहा है:—

1. जेन्डर और क्षेत्र के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्षेत्रीय प्रकृति		क्षेत्रीय प्रकृति		योग
		शहरी	ग्रामीण	
जेन्डर	पुरुष	28	23	51
		54.9%	45.1%	100.0%
		70.0%	57.5%	63.8%
	महिला	12	17	29
		41.4%	58.6%	100.0%
		30.0%	42.5%	36.3%
योग		40	40	80
		50.0%	50.0%	100.0%
		100.0%	100.0%	100.0%

शोध चूंकि स्थानीय शासन के दोनों ही स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन है अतः तालिका दर्शाती है कि शोध के दौरान कुल 80 उत्तरदाताओं (जनप्रतिनिधियों) पर अध्ययन किया गया इनमें 63.8 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता थे जबकि

* शोधार्थी, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।